भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 197

उत्तर देने की तारीख: 19.07.2021

शिक्षा में असमानता

197. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर में व्यापक असमानता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा देश के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर में एकरूपता लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में किए गए प्रयासों में सरकार को कितनी सफलता मिली है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): उच्चतर शिक्षा के लिए नीतियां तैयार करने हेतु पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा का न्यूनतम मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अपने विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाता है।

(ग) और (घ): शिक्षा समवर्ती सूची में एक विषय होने के कारण, इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच सुविचारित योजना, संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन की आवश्यकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण और उपचारात्मक भूमिका निभाती है, मंत्रालय ने योजनाबद्ध विकास के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें विभिन्न केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है।

परिणामस्वरूप शिक्षा के प्रमुख संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2015-16 में 24.5 (महिला: 23.5, पुरुष: 25.4, एससी: 19.9, एसटी: 14.2) से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 27.1 (महिला: 27.3, पुरुष: 26.9, एससी: 23.4, एसटी: 18.0)

हो गया है। विश्वविद्यालयों की संख्या 2015-16 में 799 से बढ़कर 2019-20 में 1043 हो गई है और इस प्रकार इसमें 30.5% की वृद्धि हुई है। कॉलेजों की संख्या भी 2015-16 में 39,071 से 8.4% बढ़कर 2019-20 में 42,343 हो गई है।

******